नईदुनिया

फेडरल रिजर्व गवर्नर को हटाने की राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश हुई नाकाम

सुप्रीम कोर्ट से के झटके के बाद ट्रंप बोले- हम एक्शन लेंगे

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फेडरल रिजर्व बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से हटाने के उनके प्रयास को 5-4 के बहुमत से खारिज कर दिया। यह 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद पहला ऐसा मौका है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक के किसी अधिकारी को हटाने की कोशिश की हो, और सर्वोच्च अदालत ने इसे असफल कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने ट्रंप प्रशासन के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को हटाने की मांग की गई थी, जिसने फेड गवर्नर लिसा कुक को तत्काल बर्खास्त करने से रोका था। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में फेड की स्वतंत्रता पर बार-बार हमला बोला है और अपनी कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं को परखा है। लिसा कुक फेडरल रिजर्व बोर्ड की सात सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं, जो अमेरिकी मौद्रिक नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 2038 तक चलना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिसा कुक के खिलाफ और कार्रवाई करने की धमकी दी है। उन्होंने लिखा कि हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अपराधी संयुक्त राज्य अमेरिका के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले न ले सके। उन्होंने अदालत के फैसले को पूरी तरह प्रक्रियात्मक करार दिया। ट्रंप ने कुक पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जो अभी तक साबित नहीं हुए हैं। कुक, जो फेड की पहली अश्वेत महिला गवर्नर हैं, ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ट्रंप उन्हें मौद्रिक नीति पर मतभेद के चलते हटाना चाहते हैं और इन आरोपों को बहाना बना रहे हैं। ट्रंप ने 25 अगस्त, 2025 को सोशल मीडिया पर बर्खास्तगी का पत्र पोस्ट कर कुक को हटाने का प्रयास किया था। इसके बाद, जिला न्यायाधीश जिया काब ने फैसला दिया था कि बिना नोटिस या सुनवाई के यह कदम उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोप कुक के पद संभालने से पहले के हैं और फेडरल रिजर्व अधिनियम के तहत पर्याप्त कारण नहीं माने जा सकते। कोलंबिया सर्किट अपील अदालत ने भी इस फैसले का समर्थन किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप सरकार की अपील खारिज कर दी है। फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे प्रभावशाली केंद्रीय बैंक है, जो अमेरिका सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था की ब्याज दरें तय करता है। ट्रंप की वापसी के बाद यह संस्था उनके निशाने पर रही है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का आठ साल का कार्यकाल 15 मई को समाप्त हुआ था, और उनकी जगह ट्रंप द्वारा नामित केविन वार्श को 13 मई को सीनेट ने मंजूरी दी थी और उन्होंने 22 मई को शपथ ली थी।

न्यूज ब्रीफ

जर्मनी के स्टेड शहर में अंधाधुंध गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार

बर्लिन। उत्तरी जर्मनी के स्टेड शहर में सोमवार को एक भीषण गोलीबारी की घटना में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध पुरुष को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, हमलावर ने इस दर्दनाक वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसके पीछे का मकसद अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सेंट्रल स्टेड में स्थित एक यूथ सेंटर के भीतर हुई। हैम्बर्ग शहर के पश्चिम में स्थित लगभग 50,000 की आबादी वाले इस शांत और सामान्य रूप से सुरक्षित शहर में हुई इस अचानक गोलीबारी से हर कोई सकते में है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती सूचना के आधार पर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल एक मुख्य संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में है और उससे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार, यूथ सेंटर के पास गोलीबारी हुई और सुरक्षा बल वर्तमान में शहर के केंद्र से बाहर बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। पुलिस ने एक पोस्ट में जनता से अनुरोध किया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र को छोड़ दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ल्यूनेबर्ग पुलिस हेडक्वार्टर ने भी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में जनता से उस इलाके से दूर रहने की अपील की। जांचकर्ताओं ने शुरुआत में हमले के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। बड़ी संख्या में इमरजेंसी सर्विस की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं, जिसमें पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन दल शामिल हैं।शुरुआती स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि इस हमले में एक से ज्यादा शूटर शामिल हो सकते हैं और कुछ अन्य संदिग्ध अभी भी फरार हो सकते हैं।

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची कल से भारत के तीन दिवसीय दौरे पर

टोक्यो। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची एक जुलाई से भारत के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी।

वह वहां अपने समकक्ष नरेन्द्र मोदी से मिलेंगी। जापान सरकार ने कहा कि इस दौरे का मकसद आर्थिक विकास के लिए सहयोग को आगे बढ़ाना है। जापान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली में दोनों देश आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणापत्र जारी कर सकते हैं। इसमें आर्थिक दबाव के विरोध का जिक्र होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ जैसे अहम मिनरल, सूचना और संचार तकनीक, और स्वच्छ ऊर्जा व मेडिकल सामान जैसे पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनने की उम्मीद है। पिछले साल अक्टूबर में पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के भारत दौरे की घोषणा करते हुए मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि जापान का लक्ष्य आर्थिक सुरक्षा, निवेश और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करके भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और बेहतर बनाना है। सरकार के शीर्ष प्रवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जापान और भारत के लिए मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संबंधों को मजबूत करना बहुत जरूरी है।

सऊदी अरब में क्रैश हेलिकाप्टर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का था

रियाद। सऊदी अरब के रास तनुरा में रविवार को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का

हेलिकाप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलिकाप्टर सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। हेलिकाप्टर में सवार सभी लोग सऊदी के ही नागरिक थे। हालांकि, क्रैश की वजह की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच चल रही हैं। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। यह सऊदी अरब सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में यह पूरी तरह सऊदी सरकार के नियंत्रण में आ गई। कंपनी का मुख्यालय धहरान में स्थित है। अरामको के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और यह प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा बाजार की प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। अरामको केवल कच्चे तेल का उत्पादन ही नहीं करती, बल्कि रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी सक्रिय है।

ईरान की दोटूक, कतर में अमेरिका के साथ कोई बातचीत तय नहीं, होर्मुज में हालात कुछ बेहतर हुए

तेहरान/वाशिंगटन

ईरान ने कहा है कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के साथ कोई बातचीत तय नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा उसके प्रतिनिधिमंडल के कतर दौरे का अमेरिकी अधिकारियों के साथ किसी भी बैठक से कोई लेना-देना नहीं है। ईरान का बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के उलट है। ट्रंप ने कहा कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल होर्मुज जलडमरूमध्य पर केंद्रित वार्ता में हिस्सा लेंगे। उधर, होर्मुज जलडमरूमध्य में पिछले 24 घंटे में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी और अल जजीरा न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, आने वाले दिनों में हमारी अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत या बैठक तय नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधियों के कतर जाने का ईरानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे से कोई लेना-देना नहीं है। बघाई ने जोर दिया कि बड़े समझौते पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है।

बघाई ने कहा, एमओयू के मसौदे के मुताबिक, अंतिम समझौते के लिए बातचीत की शुरुआत 14 सूत्री सहमति पत्र के क्रम संख्या 1, 4, 5, 10, और 11 में उल्लिखित बातों के लागू होने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका को ईरान के फ्रीज किए गए या रोके गए फंड और एसेट्स को आपसी सहमति से तय प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपलब्ध कराना होगा।

इस बीच, व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकाफ और ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर मंगलवार को ईरान के साथ बातचीत के लिए दोहा जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने फाक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में इसकी पुष्टि की और कहा कि यह बैठक ईरान के अनुरोध पर हो रही है। लेविट ने कहा कि ट्रंप शांति प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने ईरान से वाशिंगटन के साथ समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में दुश्मनी खत्म करने के लिए 14 सूत्री एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद तकनीकी बातचीत जारी है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने बैठक का आग्रह किया है। यह कल दोहा में होगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस सबसे पहले दोहा में होने वाली बैठक का खुलासा कर चुकी है।

हालांकि इसके बाद ईरान के सरकारी ब्राडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान ब्राडकास्टिंग ने ईरान के कानून और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेशमंत्री काज़ूम गरीबाबादी के हवाले से कहा कि इस हफ्ते कोई टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग तय नहीं है। उन्होंने कहा कि कतर के साथ बातचीत हमेशा की तरह जारी है। सनद रहे तेहरान और वाशिंगटन के बीच वार्ता में कतर मुख्य मध्यस्थ है।

अमेरिका और ईरान के अलग-अलग बयानों से मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में तनाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत को लेकर मिले-जुले संकेतों ने मिडिल ईस्ट की कूटनीति में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी इस हफ्ते कतर में मिलेंगे, लेकिन तेहरान ने इससे इनकार किया कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है।

ईरान के विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी ट्रंप के उस बयान के उलट है जिसमें कहा गया कि बातचीत मंगलवार से शुरू होगी। इन अलग-अलग बयानों ने कूटनीतिक कोशिशों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य में 24 घंटे में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। मरीन ट्रैफिक डेटा के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान 25 कमर्शियल जहाज जलडमरूमध्य से गुजरे। फारस की खाड़ी से बाहर जाने वाले जहाजों में छह आयल टैंकर और आठ कार्गो जहाज शामिल हैं, जबकि पांच टैंकर और छह कार्गो जहाज खाड़ी में दाखिल हुए।

काठमांडू में ट्रैफिक संभालने के लिए रोबोट का प्रयोग शुरू

काठमांडू

नेपाल की राजधानी काठमांडू में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए अब रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। तकनीक-आधारित पहल के तहत ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को संभालने से लेकर जागरूकता कक्षाएं संचालित करने के लिए रोबोट का परीक्षण शुरू किया है। प्रारंभिक चरण में रोबोट को उन चौक चौराहों पर प्रयोग में लाया गया है जहां सबसे अधिक ट्रैफिक जाम लगता है। राजधानी के सबसे व्यस्त चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की संख्या को कटौती कर रोबोट को रखा गया है।

इसके अलावा चालकों के लिए जागरूकता सत्र संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें विभिन्न ट्रैफिक नियम उल्लंघन के कारण दंडित किया गया है।

ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के अलावा जिन चालकों ने लेन उल्लंघन, रेड लाइट जंप, शराब पीकर वाहन चलाने, नशीले पदार्थ के प्रभाव में ड्राइविंग, तेज गति से वाहन चलाया हो उन्हें सजा के तौर पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वह काम भी रोबोट के द्वारा किया जा रहा है।

काठमांडू ट्रैफिक के एसएसपी सुरेश काफ्ले ने बताया कि रोबोट को फिलहाल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसे विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, ताकि भविष्य में वह पूरी तरह स्वतंत्र रूप से जागरूकता कक्षाएं संचालित कर सके।

ट्रैफिक पुलिस प्रतिदिन लगभग 600 ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों को जागरूकता कक्षाएं प्रदान करती है। इसके अलावा, सड़क गलत तरीके से पार करने वाले पैदल यात्रियों को शिक्षित करने के लिए भी रोबोट के उपयोग की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। एसएसपी काफ्ले ने कहा कि पूरी तरह प्रशिक्षित होने के बाद यह रोबोट ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनकर एक वर्चुअल ट्रैफिक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

पाकिस्तान के रावलपिंडी में जेल वैन से 14 कैदी भागे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 14 कैदी जेल वैन से भाग गए। पुलिस का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर भागे इन कैदियों की तलाश की जा रही है। अभी तक इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है। भागे हुए कैदियों में से चार को पकड़ लिया गया है। यह घटना रावलपिंडी के कहूटा क्षेत्र में हुई है। जियो न्यूज और दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रावलपिंडी पुलिस के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि कहूटा में जेल वैन से 14 कैदियों के भागने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान चार कैदियों को दबोच लिया गया। प्रवक्ता के अनुसार, संबंधित अधिकारियों से घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि बाकी 10 कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें काम कर रही हैं। प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि घटना से पहले वैन के अंदर कैदियों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। अदालत में पेशी के बाद कैदियों को अदियाला जेल ले जाया जा रहा था, तभी यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि वैन को चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान एक कैदी ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया। सनद रहे, पिछले साल कराची की मालिर जेल से भूकंप के कारण लोगों को बाहर निकालते समय 200 से ज्यादा कैदी भाग गए थे। इस घटना में कम से कम एक कैदी की मौत हो गई थी और कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे।

चीन की विस्तारवादी नीति : तिब्बत के जरिए नदियों को नियंत्रित कर भारत पर दबाव बनाने की साजिश

बीजिंग

पड़ोसी देशों पर दबाव बनाकर खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश साबित करने की होड़ में चीन लगातार नई साजिशें कर रहा है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बाद अब उसका मुख्य फोकस भारतीय सीमाओं और रणनीतिक क्षेत्रों पर है। इस बीच, जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ ने चीन की चालबाजियों को लेकर भारत को कड़ा अलर्ट किया है। रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार, तिब्बत पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के बाद चीन अब हिमालय के पार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर सकता है।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन इस भौगोलिक बढ़त का इस्तेमाल सीमा पार बहने वाली प्रमुख नदियों के पानी और उनके बहाव को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है, जो भारत सहित कई एशियाई देशों के लिए बड़ा जल-संकट पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तिब्बत कोई साधारण इलाका नहीं, बल्कि एशिया का भौगोलिक और रणनीतिक केंद्र है। दुनिया की छत कहे जाने वाले इस विशाल तिब्बती पठार से दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इसी रणनीतिक फायदे का लाभ उठाकर चीन भारतीय सीमा पर लद्दाख के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश (जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है) पर अपना अवैध दावा ठोकता रहता है। इसके अलावा, वैश्विक व्यापार के प्रमुख रास्ते दक्षिण चीन सागर पर अपना वर्चस्व जमाने, सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान से उलझने और ताइवान जलडमरूमध्य में लगातार सैन्य घुसपैठ करने जैसी गतिविधियों से वह पूरे क्षेत्र में अशांति फैला रहा है। मलक्का जलडमरू पर अपनी तेल निर्भरता कम करने के लिए वह हिंद महासागर में पैर पसार रहा है। भारत को घेरने की रणनीति के तहत उसने आर्थिक जाल में फंसाकर पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाहों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है।

वेनेजुएला में भूकंप से हर तरफ तबाही, हताहतों की संख्या 1,719 पहुंची, हजारों लोग अब भी लापता

कराकास (वेनेजुएला)

दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित वेनेजुएला में पांच दिन पहले आए दो भूकंपों से भारी विनाश हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़कर 1,719 हो गई है। 5,034 लोग घायल हैं और हजारों लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। आफ्टरशाक और क्षतिग्रस्त इमारतों के कारण अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।

नेशनल असेंबली अध्यक्ष जार्ज रोड्रिगेज ने सोमवार को बताया कि अब तक कम से कम 1,719 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,034 लोग घायल हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। सनद रहे 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप बुधवार शाम आए थे। इनके झटके पड़ोसी देश कोलंबिया में भी महसूस किए गए। इन्हें पिछले एक सदी में वेनेजुएला में आए सबसे विनाशकारी भूकंप माना जा रहा है।

रोड्रिग्ज ने बताया कि अमेरिकी जियोलाजिकल सर्वे का कहना है कि इस बात की 44 प्रतिशत संभावना है कि मरने वालों की कुल संख्या 10,000 या उससे ज्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन झटकों से कम से कम 22,619 लोग प्रभावित हुए हैं। कम से कम 855 इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, जिनमें से 189 पूरी तरह ढह गईं। उन्होंने कहा कि बुधवार को भूकंप आने के बाद से 609 आफ्टरशाक (भूकंप के बाद के झटके) आए हैं।राहत कार्यों में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता समूह वेनेजुएला पहुंच गए हैं। इस आपदा के बाद कई बेघर हुए लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे ज्यादा तबाही ला गुएरा राज्य, राजधानी काराकास और आसपास के इलाकों में हुई है। इजराइल की आपदा राहत टीम मंगलवार को वेनेजुएला के लिए रवाना होगी। यह घोषणा इजराइल के विदेश मंत्रालय ने की। इस टीम में मंत्रालय के सदस्यों के साथ-साथ इजराइल के होम फ्रंट कमांड के बचावकर्मी भी शामिल होंगे। बाद में नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथारिटी के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। वेनेजुएला के लिए यह सहायता इजराइल के लिए अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई सालों से कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं।

काराकास में अधिकारी बुनियादी ढांचों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। काराकास में मौजूद चाकाओ मेयर आफिस ने भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। यह काम खासकर लास पालोस ग्रांडेस इलाके में किया जा रहा है। इसके लिए वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन इमारतों पर हरा निशान है, वे रहने लायक हैं। पीला निशान मध्यम नुकसान को दर्शाता है और लाल निशान इसका प्रतीक है कि इमारत में अंदर जाना सुरक्षित नहीं है। वेनेजुएला में नुकसान हर जगह दिख रहा है। इमारतों के बाहरी हिस्सों में दरारों से लेकर सड़कों पर पड़ी बड़ी-बड़ी दरारों तक। जरूरी जांच-पड़ताल होने तक कुछ इलाके और इमारतें आम लोगों के लिए बंद रखी गई हैं।वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि विशेषज्ञ ला गुएरा, मिरांडा और काराकास में यह पता लगाने के लिए मौजूद हैं कि क्या घर रहने लायक हैं।